



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 277]
No. 277]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, जून 12, 2003/ज्येष्ठ 22, 1925
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 12, 2003/JYAISTHA 22, 1925

वित्त मंत्रालय

(कंपनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जून, 2003

सा.का.नि. 480(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के कंपनी कार्य विभाग की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं० सा०का०नि० 443 (अ), तारीख 18 अक्टूबर, 1972 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 227 की उपधारा (4क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित आदेश सं. सा.का.नि. 909 (अ), तारीख 7 सितंबर, 1988 को अधिकांत करते हुए, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, और कंपनियों के उस वर्ग के संबंध में, जिसको यह आदेश लागू होता है और अन्य आनुषंगिक विषयों की बाबत भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान (जो चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अधीन गठित किया गया है) से परामर्श करने के पश्चात् निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2003 है।

(2) यह प्रत्येक ऐसी कंपनी को, जिसके अंतर्गत अधिनियम की धारा 591 में यथा परिभाषित विदेशी कंपनी भी है, लागू होगा, निम्नलिखित को छोड़कर :-

(i) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 के खंड (ग) में यथा परिभाषित कोई बैंककारी कंपनी ;

(ii) अधिनियम की धारा 2 के खंड (21) में यथा परिभाषित कोई बीमा कंपनी ;

(iii) कोई भी कंपनी जिसे अधिनियम की धारा 25 के अधीन कार्य करने के लिए अनुज्ञप्ति दी गई है ; और

(iv) कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसकी समादत्त पूंजी और आरक्षितियां पचास लाख रुपए से अधिक नहीं हैं और जिसने कोई लोक निक्षेप स्वीकार नहीं किया है, जिस पर किसी बैंक या वित्तीय संस्था से दस लाख रुपए या अधिक का उधार बकाया नहीं है और जिसकी पांच करोड़ रुपए से अधिक व्यापारवर्ष नहीं है ।

(3) यह 1 जुलाई, 2003 को प्रवृत्त होगा ।

2. परिभाषाएं — इस आदेश में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) अभिप्रेत है ;

(ख) “चिट फंड कम्पनी”, “निधि कम्पनी” या “पारस्परिक प्रसुविधा कम्पनी” से ऐसी कम्पनी अभिप्रेत है जो किसी ऐसे संव्यवहार या ठहराव के फौरमैन या अभिकर्ता के रूप में प्रबंध, संचालन या पर्यवेक्षण के कारबार में लगी हुई है, जिसके द्वारा वह अनेक अभिदाताओं के साथ इस प्रकार करार करती है कि उनमें से प्रत्येक किसी निश्चित अवधि के लिए किश्तों की किसी निश्चित राशि का अभिदाय करेगा तथा प्रत्येक अभिदाता, अपनी बारी पर, जो लाट डालकर या नीलामी द्वारा या निविदा द्वारा या किसी अन्य ऐसी रीति में, जो कि करार में उपबंधित की जाए, अवधारित की गई हो, प्राइज रकम का हकदार होगा तथा उसके अंतर्गत वे कम्पनियां आती हैं जिनका प्रधान कारबार अपने सदस्यों से नियत निक्षेप स्वीकार करना और उन्हें धन उधार देना है ;

(ग) “वित्त कम्पनी” से ऐसी कम्पनी अभिप्रेत है, जो किसी उद्योग, वाणिज्य या कृषि के, उधार देकर या अभिदाय करके या अन्यथा, वित्तीय कारबार में लगी हुई है और उसके अन्तर्गत कोई भी ऐसी कम्पनी आती है, जो अवक्रय, पट्टा वित्त पोषण और आवासन के वित्त पोषण के कारबार में लगी हुई है ;

(घ) “विनिधान कंपनी” से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है जो केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए शेयरों, स्टाकों, बंधपत्रों, डिबेंचरों, डिबेंचर स्टाकों, जिसके अंतर्गत प्रतिभूतियां भी हैं, अथवा ऐसी ही प्रकृति की अन्य विक्रेय प्रतिभूतियों के अर्जन और धारण के कारबार या उसके लेन देन में लगी हुई है ।

(ङ) “विनिर्माता कम्पनी” से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है जो कारखाना अधिनियम, 1948 (1948

का 63) में यथा परिभाषित किसी विनिर्माण प्रक्रिया में लगी हुई है ;

- (च) “खनन कंपनी” से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है जो किसी खान की स्वामी है और उसके अंतर्गत ऐसी कंपनी आती है जो उसकी पट्टेदार या अधिमोगी के रूप में किसी खान का कारबार करती है ;
- (छ) “प्रसंस्करण कम्पनी” से, ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जो सामग्री के प्रयोग, विक्रय परित्दान सा व्ययन की दृष्टि से उसके प्रसंस्करण के कारबार में लगी हुई है ;
- (ज) “सेवा कंपनी” से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है जो दूसरों के फायदे के लिए किन्हीं सेवाओं, सुविधाओं, प्रसुविधाओं ब्यूरो और वैसे ही का प्रदाय करने, उपबंध करने, उन्हें बनाए रखने और उनके चलाने के कारबार में लगी हुई है ;
- (झ) “व्यापार कंपनी” से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है जो माल के क्रय और विक्रय के कारबार में लगी हुई है ।

3. लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में पैरा 4 और पैरा 5 में विनिर्दिष्ट विषय होंगे— लेखा परीक्षक द्वारा परीक्षित प्रत्येक ऐसी कम्पनी के लेखाओं के बारे में, जिसको यह आदेश लागू है, इस आदेश के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् किसी दिन को समाप्त होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, अधिनियम की धारा 227 के अधीन उसके द्वारा दी गई प्रत्येक रिपोर्ट में वे विषय अंतर्विष्ट होंगे जो इस आदेश के पैरा 4 और पैरा 5 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले विषय— उक्त कंपनी के, जिसको यह आदेश लागू है, लेखाओं के बारे में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में निम्नलिखित विषयों के बारे में कथन, सम्मिलित होगा, अर्थात् :-

(i) (क) क्या कंपनी पूर्ण विशिष्टियां दर्शित करने के लिए समुचित अभिलेख रख रही है जिनके अन्तर्गत परिभाषात्मक ब्यौरे और नियत आस्तियों की स्थिति भी है ;

(ख) क्या उन नियत आस्तियों की प्रबन्धक मंडल द्वारा युक्तियुक्त अन्तरालों पर अस्तित्व जांच कर ली गई है और यदि ऐसी जांच पर कोई तात्त्विक फर्क पाए गए हैं, और यदि ऐसा है तो क्या उनकी बाबत लेखा-बहियों में समुचित कार्यवाही कर ली गई है ;

(ग) यदि नियत आस्तियों के सारभूत भाग का वर्ष के दौरान व्ययन कर दिया गया है, तो क्या उसका चालू समुत्थान पर प्रभाव पड़ा है ;

(ii) (क) क्या प्रबंध मंडल द्वारा युक्तियुक्त अन्तरालों पर भास की तात्त्विक की अस्तित्व जांच कर ली गई है ;

(र) क्या प्रबंध मंडल द्वारा माल की तालिका के अस्तित्व जांच के लिए अनुसरित की जाने वाली प्रक्रियाएं कंपनी के आकार और उसके कारबार की प्रकृति के संबंध में युक्तियुक्त और पर्याप्त हैं? यदि नहीं, तो ऐसी प्रक्रियाओं में अपर्याप्तताओं की रिपोर्ट की जानी चाहिए ;

(ग) क्या कंपनी माल की तालिका का समुचित अभिलेख रख रही है और क्या अस्तित्व जांच पर कोई तात्विक फर्क पाया गया था और यदि ऐसा है, तो क्या उनके बारे में लेखा बहियों में समुचित कार्यवाही कर ली गई है ;

(iii) (क) क्या कंपनी ने धारा 301 के अधीन रखे गए रजिस्टर के अंतर्गत आने वाली कंपनियों, फर्मों या अन्य पक्षकारों को कंपनी को/से कोई प्रतिभूत या अप्रतिभूत उधार दिए हैं या लिए हैं । यदि ऐसा है, तो पक्षकारों की संख्या और संव्यवहारों में अन्तर्वर्तित रकम दें ।

(ख) क्या कंपनी द्वारा दिए गए या लिए गए प्रतिभूत या अप्रतिभूत उधारों की ब्याज की दर और अन्य निबंधन और शर्तें प्रथम दृष्ट्या कंपनी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हैं ;

(ग) क्या मूल रकम और ब्याज का संदाय भी नियमित हैं ;

(घ) यदि अतिशोध्य रकम एक लाख से अधिक है तो क्या मूल रकम और ब्याज की वसूली/संदाय के लिए कंपनी द्वारा युक्तियुक्त कदम उठाए गए हैं ;

(iv) क्या माल की तालिका और नियत आस्तियों के क्रय के लिए और माल के विक्रय के लिए कंपनी के आकार और उसके कारबार की प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया विद्यमान है । क्या आंतरिक नियंत्रण में प्रमुख दुर्बलताओं को सही करने में लगातार असफल रही है ;

(v) (क) क्या संव्यवहार जिन अधिनियम की धारा 301 के अनुसरण में रखे गए रजिस्टर में दर्ज किए जाने आवश्यक है इस प्रकार प्रविष्ट कर दिए गए हैं ;

(ख) क्या इन संव्यवहारों में से प्रत्येक संव्यवहार ऐसे मूल्यां पर किए गए हैं जो सुसंगत समय पर प्रयोजित बाजार मूल्यों को ध्यान में रखते हुए युक्तियुक्त हैं ;

(ग) जानकारी केवल किसी पक्षकार और किसी एक वित्तीय वर्ष की बाबत पांच लाख के अधिक के संव्यवहारों की दशा में अपेक्षित है) ।

(vi) क्या कंपनी ने जनता से निक्षेप स्वीकार किए हैं तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए अधिनियम की धारा 58क और 58कक के उपबंधों और उसके अधीन दिए गए निर्देशों का पालन किया गया है । यदि नहीं, तो उल्लंघनों की

प्रकृति का कथन करें ; यदि कंपनी द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है तो क्या उसका अनुपालन किया गया है या नहीं ?

(vii) सूचीबद्ध कंपनियों और/या अन्य कंपनियों की दशा में जिनकी संबंधित वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में समादत्त पूंजी और आरक्षितियां 50 लाख रुपए से अधिक हैं या संबंधित वित्तीय वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती लगातार तीन वर्षों की अवधि के लिए औसत वार्षिक आवर्त पांच करोड़ रुपए से अधिक है, क्या कंपनी की उसके आकार और उसके कारबार की प्रकृति के अनुरूप कोई आंतरिक लेख पद्धति है ;

(viii) जहां केन्द्रीय सरकार ने अधिनियम की धारा 209 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन लागत अभिलेख का रखा जाना विहित किया गया है, वहां क्या ऐसे लेखा और अभिलेख बनाए और रखे गए हैं ;

(ix) (क) क्या कंपनी निर्विवाद कानूनी शोध्यों जिसके अंतर्गत भविष्य निधि, विनिधानकर्ता शिक्षा, संरक्षण निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, विक्रय कर, धन कर, सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर और समुचित प्राधिकारियों के साथ अन्य कानूनी शोध्यों का निक्षेप नियमित रूप से कर रही है और यदि नहीं तो बकाया कानूनी शोध्यों की बकाया की मात्रा जो उस तारीख से जिससे वे संदेय हुई, छह मास से अधिक की अवधि के लिए संबंधित वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को बकाया थी, लेखा परीक्षक द्वारा उपदर्शित की जाएगी ।

(ख) यदि विक्रय कर/आयकर/सीमा कर/धन कर/उत्पाद शुल्क/उपकर के शोध्यों का किसी विवाद के कारण निक्षेप नहीं किया गया है तब अंतर्ग्रस्त ऐसी रकम और फोरम का जहां विवाद लंबित है उल्लेख किया जाए ।

(विभाग को केवल अभ्यावेदन किया जाना विवाद नहीं माना जाएगा)

(x) क्या किसी ऐसी कंपनी की दशा में जो कम से कम पांच वर्ष से रजिस्ट्रीकृत है उस वित्तीय वर्ष के अंत में उसकी संचित हानियां उसके शुद्ध मूल्य के 50 प्रतिशत से कम नहीं हैं और क्या उसको ऐसे वित्तीय वर्ष में और ऐसे वित्तीय वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में भी नकद हानियां उपगत हुई हैं ;

(xi) क्या कंपनी ने किसी वित्तीय संस्था या बैंक या डिबेंचर धारकों को शोध्यों के प्रतिसंदाय में व्यतिक्रम किया है? यदि हां तो व्यतिक्रम की अवधि और रकम की रिपोर्ट की जाए ;

(xii) क्या ऐसे मामलों में जहां कंपनी ने शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर प्रतिभूति के आधार पर उधार और अग्रिम दिए हैं उनके पर्याप्त दस्तावेज और अभिलेख रखे हैं ; यदि नहीं तो उन कमियों को उपदर्शित किया जाए ।

(xiii) क्या निधि/ पारस्परिक प्रसुविधा निधि/सोसाइटी की बाबत चिटनिधि को लागू किसी विशेष कानून के उपबंधों का सम्यकतः अनुपालन किया गया है ;

(क) क्या शुद्ध स्वामित्व की निधियों में निक्षेप दायित्व का अनुपात तुलन पत्र की तारीख को 1: 20 से अधिक है ;

(ख) क्या कंपनी ने आस्तियों के च्युत मानक/चूक/हानि के प्रति आय मान्यता और व्यवस्था पर प्रज्ञापूर्ण संनियमों का पालन किया है ;

(ग) क्या कंपनी के पास उधार प्रस्तावों/अनुरोधों के आंकन उधार की आवश्यकताओं और उधार लेने वालों की प्रतिसंदाय क्षमता के लिए पर्याप्त प्रक्रियाएं हैं ;

(घ) क्या निधि द्वारा दिए गए विभिन्न उधारों की प्रतिसंदाय अनुसूची उधार लेने वालों की प्रतिसंदाय क्षमता पर आधारित है और वह उधार की रकम की वसूली के लिए सहायक हो सकेगी ।

(xiv) यदि कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों डिबेंचरों और अन्य विनिधानों का लेन-देन या व्यापार करती है, तो क्या संव्यवहारों और संविदाओं के समुचित अभिलेख रखे गए हैं और क्या उनमें समय पर प्रविष्टियां की गई हैं, कंपनी द्वारा शेयर, प्रतिभूतियां डिबेंचर और अन्य प्रतिभूतियां भी अपने ही नाम में, उस छूट के, यदि कोई हो, विस्तार तक के सिवाय धारण किए हैं, जो अधिनियम की धारा 49 के अधीन दी गई है ;

(xv) क्या कंपनी ने बैंक या वित्तीय संस्थाओं से अन्य व्यक्तियों द्वारा लिए गए उधारों के लिए कोई गारंटी दी है जिसके निबंधन और शर्तें कंपनी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हैं ;

(xvi) क्या कालिक उधार उन्हीं प्रयोजनों के लिए उपयोग किए गए हैं जिसके लिए उधार अभिप्राप्त किए गए थे ;

- (vii) क्या अल्पकालिक आधार पर जुटाई गई निधियों का दीर्घकालिक विनिधान के लिए और विपर्ययेन उपयोग किया गया है ; यदि हां तो प्रकृति और रकम उपदर्शित की जानी है ;
- (xviii) क्या कंपनी ने पक्षकारों और अधिनियम की धारा 301 के अधीन रखे गए रजिस्टर के अंतर्गत आने वाली कंपनियों के लिए शेयरों का कोई अधिमानी आबंटन किया है और यदि ऐसा है तो क्या वह कीमत जिसपर शेयर निर्गमित किए गए हैं, कंपनी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हैं ;
- (xix) क्या 'प्रतिभूतियां निर्गमित डिबेंचरों की बाबत सृजित की गई हैं ;
- (xx) क्या प्रबंध मंडल ने लोक निर्गमनों द्वारा जुटाए गए धन को उपयोग के अंत में प्रकट किया है और उसका सुत्यापन कर दिया गया है ;
- (xxi) क्या कंपनी पर या कंपनी द्वारा किसी कपट का पता लगा है या उसकी रिपोर्ट की गई है, यदि हां तो प्रकृति और अंतर्ग्रस्त रकम उपदर्शित की जानी है ।

5. अननुकूल या विशेषित उत्तरों के लिए कारणों का कथन किया जाए— जहां लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में, पैरा 4 में निर्दिष्ट प्रश्नों में से किसी का उत्तर अननुकूल या विशेषित है, वहां लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में, यथास्थिति, ऐसे अननुकूल या विशेषित उत्तर के लिए कारणों का कथन भी किया जाएगा । जहां-लेखा परीक्षक किसी विशिष्ट प्रश्न के उत्तर में कोई राय व्यक्त करने में असमर्थ है, वहां उसकी रिपोर्ट में यह तथ्य इस बात के कारणों सहित उपदर्शित किया जाएगा कि उसके लिए ऐसे प्रश्न का उत्तर देना क्यों संभव नहीं है ।

[फा. सं. 2/28/2002-सीएल. V]

राजीव महर्षि, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th June, 2003

G.S.R. 480(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (4A) of Section 227 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), read with the Notification of the Government of India in the Department of Company Affairs, number G.S.R. 443(E), dated 18th October, 1972, as amended from time to time and in supersession of order number G.S.R. 909(E), dated 7th September, 1988, published in the Gazette of India, part II, section 3, sub section (i), except as respects things done or omitted to be done before the supersession, and after consultation with the Institute of Chartered Accountants of India [constituted under the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949)], in regard to class of companies to which this order applies and other ancillary matters, the Central Government hereby makes the following Order, namely:-

1. **Short title, application and commencement.** – (1) This order may be called the **Companies (Auditor's Report) Order, 2003**.

(2) It shall apply to every company including a foreign company as defined in section 591 of the Act, except the following :-

- (i) a Banking company as defined in clause (c) of section 5 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949);
- (ii) an insurance company as defined in clause (21) of section 2 of the Act;
- (iii) a company licensed to operate under section 25 of the Act; and

- (iv) a private limited company with a paid up capital and reserves not more than fifty lakh rupees and has not accepted any public deposit and does not have loan outstanding ten lakh rupees or more from any bank or financial institution and does not have a turnover exceeding five crore rupees.

(3) It shall come into force on the 1st day of July, 2003.

2. Definitions. – In this Order, unless the context otherwise requires,-

- (a) "Act" means the Companies Act, 1956 (1 of 1956);
- (b) "chit fund company", "nidhi company" or "mutual benefit company" means a company engaged in the business of managing, conducting or supervising as a foreman or agent of any transaction or arrangement by which it enters into an agreement with a number of subscribers that every one of them shall subscribe to a certain sum of instalments for a definite period and that each subscriber, in his turn, as determined by lot or by auction or by tender or in such other manner as may be provided for in the agreement, shall be entitled to a prize amount, and includes companies whose principal business is accepting fixed deposits from, and lending money to, members;
- (c) "finance company" means a company engaged in the business of financing, whether by making loans or advances or otherwise, of any industry, commerce or agriculture and includes any company engaged in the business of hire-purchase, lease financing and financing of housing;
- (d) "investment company" means a company engaged in the business of acquisition and holding of, or dealing in, shares, stocks, bonds, debentures, debenture stocks, including securities issued by the Central or any State Government or by any local authority, or in other marketable securities of a like nature;

- (e) "manufacturing company" means a company engaged in any manufacturing process as defined in the Factories Act, 1948 (63 of 1948);
 - (f) "mining company" means a company owning a mine, and includes a company which carries on the business of a mine either as a lessee or occupier thereof;
 - (g) "processing company" means a company engaged in the business of processing materials with a view to their use, a sale, delivery or disposal;
 - (h) "service company" means a company engaged in the business of supplying, providing, maintaining and operating any services, facilities, conveniences, bureaux and the like for the benefit of others;
 - (i) "trading company" means a company engaged in the business of buying and selling goods.
3. **Auditor's report to contain matters specified in paragraphs 4 and 5.** — Every report made by the auditor under section 227 of Act, on the accounts of every company examined by him to which this Order applies for every financial year ending on any day on or after the commencement of this Order, shall contain the matters specified in paragraphs 4 and 5.
4. **Matters to be included in the auditor's report.** — The auditor's report on the account of a company to which this Order applies shall include a statement on the following matters, namely :-
- (i) (a) whether the company is maintaining proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of fixed assets;
 - (b) whether these fixed assets have been physically verified by the management at reasonable intervals; whether any material discrepancies were noticed on such verification and if so, whether the same have been properly dealt with in the books of account;

- (c) If a substantial part of fixed assets have been disposed off during the year, whether it has affected the going concern;
- (ii) (a) whether physical verification of inventory has been conducted at reasonable intervals by the management;
- (b) are the procedures of physical verification of inventory followed by the management reasonable and adequate in relation to the size of the company and the nature of its business. If not, the inadequacies in such procedures should be reported;
- (c) whether the company is maintaining proper records of inventory and whether any material discrepancies were noticed on physical verification and if so, whether the same have been properly dealt with in the books of account;
- (iii) (a) has the company either granted or taken any loans, secured or unsecured to/from companies, firms or other parties covered in the register maintained under section 301 of the Act. If so, give the number of parties and amount involved in the transactions.
- (b) whether the rate of interest and other terms and conditions of loans given or taken by the company, secured or unsecured, are prima facie prejudicial to the interest of the company;
- (c) whether payment of the principal amount and interest are also regular;
- (d) If overdue amount is more than one lakh, whether reasonable steps have been taken by the company for recovery/payment of the principal and interest;
- (iv) is there an adequate internal control procedure commensurate with the size of the company and the nature of its business, for the purchase of inventory and

fixed assets and for the sale of goods. Whether there is a continuing failure to correct major weaknesses in internal control;

- (v) (a) whether transactions that need to be entered into a register in pursuance of section 301 of the Act have been so entered;
- (b) whether each of these transactions have been made at prices which are reasonable having regard to the prevailing market prices at the relevant time;

(This information is required only in case of transactions exceeding the value of five lakh rupees in respect of any party and in any one financial year).

- (vi) in case the company has accepted deposits from the public, whether the directives issued by the Reserve Bank of India and the provisions of sections 58A and 58AA of the Act and the rules framed there under, where applicable, have been complied with. If not, the nature of contraventions should be stated; If an order has been passed by Company Law Board whether the same has been complied with or not?
- (vii) in the case of listed companies and/or other companies having a paid-up capital and reserves exceeding Rs.50 lakhs as at the commencement of the financial year concerned, or having an average annual turnover exceeding five crore rupees for a period of three consecutive financial years immediately preceding the financial year concerned, whether the company has an internal audit system commensurate with its size and nature of its business;
- (viii) where maintenance of cost records has been prescribed by the Central Government under clause (d) of sub-section (1) of section 209 of the Act, whether such accounts and records have been made and maintained;
- (ix) (a) is the company regular in depositing undisputed statutory dues including Provident Fund, Investor Education and Protection Fund, Employees' State

Insurance, Income-tax, Sales-tax, Wealth Tax, Custom Duty, Excise Duty, cess and any other statutory dues with the appropriate authorities and if not, the extent of the arrears of outstanding statutory dues as at the last day of the financial year concerned for a period of more than six months from the date they became payable, shall be indicated by the auditor.

(b) in case dues of sales tax/income tax/custom tax/wealth tax/excise duty/cess have not been deposited on account of any dispute, then the amounts involved and the forum where dispute is pending may please be mentioned.

(A mere representation to the Department shall not constitute the dispute).

- (x) whether in case of a company which has been registered for a period not less than five years, its accumulated losses at the end of the financial year are not less than fifty per cent of its net worth and whether it has incurred cash losses in such financial year and in the financial year immediately preceding such financial year also;
- (xi) whether the company has defaulted in repayment of dues to a financial institution or bank or debenture holders? If yes, the period and amount of default to be reported;
- (xii) whether adequate documents and records are maintained in cases where the company has granted loans and advances on the basis of security by way of pledge of shares, debentures and other securities; If not, the deficiencies to be pointed out.
- (xiii) whether the provisions of any special statute applicable to chit fund have been duly complied with? In respect of nidhi/ mutual benefit fund/societies;
 - (a) whether the net-owned funds to deposit liability ratio is more than 1:20 as on the date of balance sheet;
 - (b) whether the company has complied with the prudential norms on income recognition and

- provisioning against sub-standard/default/loss assets;
- (c) whether the company has adequate procedures for appraisal of credit proposals/requests, assessment of credit needs and repayment capacity of the borrowers;
 - (d) whether the repayment schedule of various loans granted by the nidhi is based on the repayment capacity of the borrower and would be conducive to recovery of the loan amount;
- (xiv) if the company is dealing or trading in shares, securities, debentures and other investments, whether proper records have been maintained of the transactions and contracts and whether timely entries have been made therein; also whether the shares, securities, debentures and other securities have been held by the company, in its own name except to the extent of the exemption, if any, granted under section 49 of the Act;
- (xv) whether the company has given any guarantee for loans taken by others from bank or financial institutions, the terms and conditions whereof are prejudicial to the interest of the company;
- (xvi) whether term loans were applied for the purpose for which the loans were obtained;
- (xvii) whether the funds raised on short-term basis have been used for long term investment and vice versa; If yes, the nature and amount is to be indicated;
- (xviii) whether the company has made any preferential allotment of shares to parties and companies covered in the Register maintained under section 301 of the Act and if so whether the price at which shares have been issued is prejudicial to the interest of the company;
- (xix) whether securities have been created in respect of debentures issued?

- (xx) whether the management has disclosed on the end use of money raised by public issues and the same has been verified;
- (xxi) whether any fraud on or by the company has been noticed or reported during the year; If yes, the nature and the amount involved is to be indicated.

5. Reasons to be stated for unfavourable or qualified answers. – Where, in the auditor's report, the answer to any of the questions referred to in paragraph 4 is unfavourable or qualified, the auditor's report shall also state the reasons for such unfavourable or qualified answer, as the case may be. Where the auditor is unable to express any opinion in answer to a particular question, his report shall indicate such fact together with the reasons why it is not possible for him to give an answer to such question.

[F. No. 2/28/2002-CL. V]

RAJIV MEHRISHI, Jt. Secy.